सच्चाई के दम पर जोश के साथ...

प्रधान संपादकः रतन प्रकाश सिंह

www.swarajindianews.com

swarajindianews swarajindianews

स्वराज इंडिया

दैनिक सांध्यकालीन

कानपुर, शुक्रवार, 17 अक्टूबर, 2025

वर्षः 02, अंकः 275, पृष्ठः 8+4, मूल्यः ₹ 2/-

» Pg12 प्रत्येक बच्चे में समाज को बदलने की क्षमताः योगी

इनसाइड गैंगरेप के आरोपी सपा नेता मोईद अहमद को मिली... » Pg11

मासूम से हैवानियत मामले में कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला

गैंगरेप के बाद हत्या के दोषियों को फांसी

दो हैवानों ने ताजनगरी को किया शर्मसार, बच्ची का शव देखकर कांप गई थी रूह, फिरौती मांगने पर खुला था राज

» वरिष्ठ संवाददाता, स्वराज इंडिया।

आगरा। रिश्ते के चाचा ने दोस्त के साथ मिलकर घर के बाहर खेल रही पांच वर्षीय बालिका का अपहरण कर दुष्कर्म के बाद हत्या और परिवार से छह लाख रुपये की फिरौती मांगी थी। मामले में न्यायालय ने चाचा और उसके साथी को दोषी माना है। अदालत ने बीते बृहस्पतिवार को दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए फांसी की सजा सुनाई। दोषी गांव फरेरा निवासी अमित और होलीपुरा निवासी निखिल पर 4.50 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। दोषियों में से अमित बच्ची का रिश्तेदार है। न्यायालय ने अपराध को जघन्य और घृणित माना है।

आगरा : कानून के शिकंजे में दरिंदे

घटना 18 मार्च 2024 की है। पिता ने रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि उनकी बच्ची पड़ोस में रहने वाले बच्चे के साथ घर के पास ही खेलने गई थी। देर शाम साथ खेलने वाला बच्चा अपने घर लौट आया, लेकिन बच्ची नहीं लौटी। परिजन ने काफी तलाश की, लेकिन उसका पता नहीं चला। पुलिस को सूचना देकर आसपास के क्षेत्र तलाशा भी, पर सफलता नहीं मिली। दूसरे दिन बालिका के पिता को फोन कर 6 लाख रुपये की फिरौती की मांगी गई। पिता ने आरोपियों से बेटी से बात कराने के लिए कहा तो आरोपी बोले कि वह बेहोश है। उन्होंने शिकोहाबाद आकर फिरौती के रकम देने को कहा। पुलिस ने शक के आधार पर बालिका के रिश्तेदार अमित और उसके दोस्त निखिल को हिरासत में लिया। सख्ती से पूछताछ की तो दोनों ने अपराध कबूल लिया।

दोनों की निशानदेही पर गांव से एक किमी दूर सरसों के खेत से बच्ची का शव बरामद किया गया। इसके बाद दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर मुकदमे में धाराएं बढ़ाई गईं।

तत्कालीन थानाध्यक्ष बाह केस के विवेचक थे। उन्होंने घटना के एक महीने बाद ही फिरौती के लिए अपहरण, हत्या, अप्राकृतिक कृत्य, सामूहिक दुष्कर्म, साक्ष्य नष्ट करने और पॉक्सो एक्ट के तहत अदालत में आरोपपत्र प्रेषित किया था। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 18 गवाह पेश किए गए। बृहस्पितवार को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट सोनिका चौधरी ने दोनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए फांसी की सजा सुनाई।

कुकर्मों की सजा मिली तो दहाड़ मारकर रोने लगे पापी

बालिका का शव देखकर गांव के लोगों के साथ पुलिसकर्मियों की भी रूह कांप गई। उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म और कुकर्म दोनों किया गया था। शरीर के हर हिस्से पर चोटों के निशान थे। पुलिस ने मजबूत साक्ष्यों के साथ एक माह के अंदर चार्जशीट न्यायालय में प्रस्तुत कर दी थी। न्यायालय ने तत्काल मुकदमे की सुनवाई शुरू कर दी थी। एडीजीसी सुभाष गिरी ने मामले में 18 गवाहों के बयान कराए और साक्ष्यों के साथ मजबूत तर्क दिए। इसके आधार पर न्यायालय ने जघन्य अपराध पर अपना फैसला सुनाया। फैसला सुनते ही आरोपित न्यायालय में दहाड़े मारकर रोने हुए माफी मांगने लगे।

संभल हिंसा के मास्टरमाइंड मुल्ला अफरोज पर लगी रासुका

» संभल, स्वराज इंडिया ब्यूरो।

यूपी के संभल हिंसा के मामले में पुलिस ने महत्वपूर्ण कार्रवाई की है। हिंसा के मुख्य आरोपी शारिक साठा गैंग के सदस्य मुल्ला अफरोज पर रासुका लागू किए जाने के बाद अब शारिक साठा और अन्य आरोपियों के विरुद्ध भी इसी तरह की प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी की जा रही है। शारिक साठा के अंतरराष्ट्रीय ठिकानों का पता लगाने के लिए विभिन्न एजेंसियों की मदद ली जा रही है और उसे इंटरपोल के माध्यम से भारत लाने की कोशिश की जा रही है।

एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने बताया कि मुरादाबाद जेल में बंद मुल्ला अफरोज को रासुका के तहत छह महीने के लिए निरूद्ध किया गया है। इसे अधिकतम 12 माह तक बढ़ाया जा सकता है। मुल्ला अफरोज पर लूट, हत्या के प्रयास और अन्य आपराधिक मामलों के अलावा वर्ष 2014-15 में सपा विधायक इकबाल महमूद के आवास पर फायरिंग करने का भी आरोप है। कुल मिलाकर उसके खिलाफ 11 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं।

एनएचएआई की अनदेखी से भौंती-रनियां अकबरपुर हाईवे बन गया डेथ कॉरिडोर

जगह जगह अवैध पार्किंग, इंजीनियरिंग की खामी और अतिक्रमण से रोज़ छीन रहा जिंदगियां

अनूप अवस्थी

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर।नेशनल हाईवे पर हर कुछ किलोमीटर पर हादसेज सड़क पर खून के धब्बे और एनएचएआई के अफसर मौन! भौंती से लेकर रनियां और अकबरपुर तक का पूरा हाइवे मौत का जाल बन चुका है। यह वो रास्ता है जहाँ सफर करने वाला हर व्यक्ति दुआ करता है – कहीं सुरक्षित पहुंच जाएं।जनता की मांग कि एनएचएआई जागो, नहीं तो ये सड़कें श्मशान बन जाएंगी।हर हादसे के बाद प्रशासन बयान देता है, जांच की बात करता है – लेकिन न रेलिंग बदली, न सिग्नल लगे, न पार्किंग रुकी।

लोगों का गुस्सा चरम पर है कि हम टैक्स देते हैं, टोल देते हैं, लेकिन क्या हमारी जान की कोई कीमत नहीं?

अकबरपुर फ्लाईओवर बना 'ब्लाइंड डेथ पॉइंट'

अकबरपुर कोतवाली रोड पर फ्लाईओवर की डिज़ाइन ही मौत बुला रही है। ऊँची सीमेंटेड रेलिंग ने सर्विस लेन और फ्लाईओवर के बीच ब्लाइंड स्पॉट बना दिया है। सर्विस लेन से चढ़ते वाहन चालकों को ऊपर से आती गाड़ियां दिखती ही नहीं।

जरा-सी चूक, और सामने ट्रक का पहिया!

चार दिन पहले मासूम शगुन और उसके भाई कृष्णा की मौत इसी ब्लाइंड स्पॉट ने निगल ली। पीछे से आता ट्राला दिखा ही नहीं। कुछ सेकंड में ज़िंदगी खत्म, परिवार बर्बाद।

फ्लाईओवर की कंक्रीट रेलिंग कोतवाली से महज़ 300 मीटर पहले अधूरी छोड़ दी गई है — यहीं सर्विस लेन हाईवे में मर्ज होती है। परिणाम- दोनों दिशाओं का ट्रैफिक आमने-सामने भिड़ता है। विशेषज्ञ कह रहे हैं — यह डिज़ाइन नहीं, मौत का आमंत्रण है।कानपुर से औरैया के बीच अन्य सभी फ्लाईओवर पर वायर रेलिंग लगी है, मगर अकबरपुर में पूरी दीवार बना दी गई। विज़ीबिलिटी जीरो!

खास खबर

अकबरपुर में इसी जगह पर दो मासूम बच्चों की अपने दादा के सामने जान चली गई

» रोज हो रहे हादसे फिर भी अफसर बरत रहे घोर लापरवाही

भौंती से रनियां तक हाईवे किनारे अवैध पार्किंग का साम्राज्य

एनएचएआई की मिलीभगत से हाईवे किनारे अवैध ट्रक पार्किंग धड़ल्ले से चल रही है। बड़े ट्राले और कंटेनर सर्विस लेन और साइड पटरी पर कब्जा जमाए हैं। इस अव्यवस्था के बीच तेज रफ्तार वाहन बचने के चक्कर में या तो टकरा जाते हैं या पलट जाते हैं।

लोगों का सवाल साफ है — एनएचएआई वसूली तो कर रही, पर सुरक्षा क्यों नहीं?

सिग्नल सिस्टम और झरोखेदार रेलिंग ही बचा सकती है जानें

ट्रैफिक विशेषज्ञों के मुताबिक, अगर फ्लाईओवर पर ग्रीन-रेड सिग्नल सिस्टम लगाया जाए और रेलिंग को झरोखेदार या पारदर्शी बनाया जाए तो हादसों पर अंकुश लग सकता है। मगर फिलहाल न कोई प्लान, न कोई पहल।

अतिक्रमण ने सर्विस लेन को बनाया जाम पॉकेट

बारा टोल के संयुक्त महाप्रबंधक मनोज शर्मा भी मानते हैं कि फ़सर्विस लेन दुकानदारों के अवैध कब्जे में है। कई बार हटाया गया, मगर फिर वही हाल।इस अराजकता में वाहनों को अचानक हाईवे पर चढ़ना पड़ता है — और वहीं होती है मौत की दस्तक। इसके बाद भी हाइवे के जिम्मेदार अनजान बने हुए हैं।

अंबेडकर प्रतिमा तालाब में फेंकी, संदिग्ध युवक हिरासत में

» एसीपी ने नई प्रतिमा लगाने का दिया आश्वासन

»प्रमुख संवाददाता स्वराज इंडिया

कानपुर। सेन पश्चिम पारा गांव में शुक्रवार सुबह अराजक तत्वों ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को चबूतरे से उखाड़कर पास के तालाब में फेंक दिया। घटना की जानकारी मिलते ही क्षेत्र में आक्रोश फैल गया और बड़ी संख्या में लोग एकत्र होकर कार्रवाई की मांग करने लगे। सूचना पर थाना प्रभारी प्रदीप कुमार सिंह और एसीपी घाटमपुर कृष्णकांत यादव मौके पर पहुंचे। पुलिस ने तालाब से क्षतिग्रस्त प्रतिमा को निकलवाया और अस्थायी रूप से दोबारा चबूतरे पर रखवाया। वहीं एसीपी कृष्णकांत यादव ने लोगों को नई प्रतिमा स्थापित कराने और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई का आश्वासन देकर स्थिति को शांत कराया।पुलिस ने एक संदिग्ध युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। एहतियात के तौर पर गांव में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया है।

संत समाज ने गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करने की मांग उठाई

»प्रमुख संवाददाता दैनिक स्वराज इंडिया

जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री को भेजा गया ज्ञापन

कानपुर। शुक्रवार को गौ संरक्षण और सनातन संस्कृति के सम्मान को लेकर संत समाज एकजुट दिखा। प्रसिद्ध संत गूगल गोल्डन बाबा स्वामी मनोजानंद जी महाराज और विश्व बैंक बर्रा सेक्टर-डी स्थित सिद्धेश्वर गणेश मंदिर के महंत धर्मेंद्र त्रिपाठी 'जय गणेश' ने जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को ज्ञापन सौंपकर गौ माता को 'राष्ट्रमाता' घोषित करने की मांग की।

संत समाज का कहना है कि गौ माता भारतीय संस्कृति की आत्मा हैं, जिनमें 33 कोटि देवी-देवताओं का वास माना गया है। उन्होंने कहा कि जब तक गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा नहीं दिया जाता, तब तक भारत की आध्यात्मिक पहचान अधूरी रहेगी। गूगल गोल्डन बाबा ने कहा सनातन धर्म में अनादिकाल से गौमाता की पूजा होती आई है। आज समय आ गया है कि सरकार उन्हें केवल 'पशु' नहीं बल्कि 'राष्ट्र की माता' के रूप में मान्यता दे। गौ सेवा ही राष्ट्र सेवा है।फ़इस अवसर पर संत समाज ने जिलाधिकारी के दीर्घायु और मंगल की भी कामना की। महंत धर्मेंद्र त्रिपाठी ने कहा कि गौ संरक्षण को संवैधानिक दर्जा मिलना चाहिए ताकि देशभर में गोवंश की रक्षा सुनिश्चित की जा सके। ज्ञापन देने के दौरान बड़ी संख्या में संत, भक्त और सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद रहे। इनमें दण्डी आश्रम के प्रकाशानंद महाराज, के.बी. सिंह, अनिल मिश्रा, कपिल केसरवानी, राहुल सेंगर, सौरभ द्विवेदी, अनुज रजावत, बड़वा ठाकुर, घनश्याम मिश्रा, सुशील राजपूत, आशुतोष शुक्ला, एड. जितेंद्र, लालू तिवारी, निक्कू तिवारी, कपिल देव केसरवानी और सतेंद्र सिंह यादव शामिल रहे।संतों ने कहा कि यदि गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा मिलता है, तो न केवल गौवंश की सुरक्षा मजबूत होगी, बल्कि भारत की सांस्कृतिक विरासत को भी वैश्विक स्तर पर नई पहचान मिलेगी।

नगर निगम में ताबड़तोड़ समीक्षा बैठकें जारी

नवागंतुक नगर आयुक्त अर्पित उपाध्याय ने मीटिंग कर दी सख्त चेतावनी, 24 घंटे में शिकायतों के निस्तारण का निर्देश

» स्वराज इंडिया न्यूज़ ब्यूरो

कानपुर। कानपुर नगर निगम में नए नगर आयुक्त अर्पित उपाध्याय, आई.ए.एस. के कार्यभार संभालने के बाद लगातार ताबड़तोड़ समीक्षा बैठकों का दौर जारी है। नगर आयुक्त ने शहर की व्यवस्थाओं को चुस्त-दुरुस्त करने और जनहित से जुड़े कार्यों में तेजी लाने के उद्देश्य से एक के बाद एक विभागीय समीक्षा बैठकों का सिलसिला शुरू कर दिया है।

नगर निगम सभागार में आयोजित बैठक में मार्ग प्रकाश विभाग की कार्यप्रणाली की विस्तृत समीक्षा की गई। बैठक में अपर नगर आयुक्त (प्रथम), वरिष्ठ प्रभारी अधिकारी, अभियंता गण एवं कंसल्टेंट मौजूद रहे। बैठक के दौरान नगर आयुक्त ने फील्ड स्तर पर कार्य निष्पादन, शिकायतों के निस्तारण और स्टोर में उपलब्ध सामग्री के उपयोग की जानकारी ली।

समीक्षा में पाया गया कि कुछ अभियंताओं द्वारा जनशिकायतों के निस्तारण में लापरवाही बरती जा रही है, जिस पर नगर आयुक्त ने नाराजगी व्यक्त करते हुए संबंधित अधिकारियों को कड़ी चेतावनी दी। उन्होंने निर्देश दिया कि सभी शिकायतों का निस्तारण 24 घंटे के भीतर सुनिश्चित किया जाए, अन्यथा संबंधित कर्मियों के विरुद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

नगर आयुक्त ने यह भी आदेश दिए कि शिकायतों की सतत मॉनिटरिंग हेतु एक प्रभावशील टीम गठित की जाए और प्रतिदिन की रिपोर्ट सीधे नगर आयुक्त कार्यालय में प्रस्तुत की जाए।

इसी क्रम में शाम 5 बजे विज्ञापन विभाग की समीक्षा बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में नगर आयुक्त ने विभागीय कार्यों की प्रगति,

संसाधन और कार्मिक उपलब्धता पर चर्चा की। प्रभारी अधिकारी ने अवगत कराया कि सीमित संसाधनों के बावजूद शहरभर में अवैध बैनर, पोस्टर और यूनिपोल हटाने की कार्यवाही लगातार की जा रही है। नगर आयुक्त ने निर्देश दिए कि विज्ञापन विभाग के समस्त कार्य पूर्ण पारदर्शिता के साथ और मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) के अनुरूप ही संपादित किए जाएं। उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी कि लोकहित के कार्यों में किसी भी प्रकार की शिथिलता या उदासीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

नगर आयुक्त अर्पित उपाध्याय के पदभार ग्रहण करने के बाद से ही नगर निगम में प्रशासनिक सख्ती और जवाबदेही की नई शुरुआत हुई है। लगातार समीक्षा बैठकों और स्पष्ट दिशा–निर्देशों से शहर की व्यवस्थाओं में सुधार की उम्मीद जताई जा रही है।

सरकारी ज़मीन पर कब्जे की पुष्टि, फिर भी आधी-अधूरी कार्रवाई

» **भ्रष्ट लेखपाल और भू-माफिया का गठजोड़ उजागर अब तक मुकदमा क्यों नहीं?**

» **सुरार कब्जा कांड में नायब तहसीलदार की आधी कार्रवाई पर उठ रहे सवाल**

» प्रमुख संवाददाता स्वराज इंडिया

कानपुर। सदर तहसील के ग्राम पंचायत सुरार में सरकारी ऊसर भूमि पर अवैध कब्जे और प्लॉटिंग के मामले ने नया मोड़ ले लिया है। सदर एसडीएम के आदेश पर राजस्व विभाग की टीम ने आराजी संख्या 607, 608, 610 और 613 में से केवल आराजी संख्या 608 के एक छोटे हिस्से पर बुलडोज़र चलाकर भूमि को कब्जे से मुक्त कराया, लेकिन अधिकांश भूभाग अब भी भू-माफियाओं के कब्जे में है। इस अधूरी कार्रवाई से प्रशासन की निष्पक्षता और मंशा दोनों पर सवाल उठने लगे हैं।

ग्राम प्रधान ने अचानक ली शिकायत वापस

ग्राम प्रधान पंकज यादव ने एसडीएम सदर को दी तहरीर में आरोप लगाया था कि वीर बहादुर यादव और महेंद्र यादव नामक भू–माफियाओं ने ऊसर भूमि पर कब्जा कर अवैध प्लॉटिंग शुरू की है।उन्होंने मौजूदा लेखपाल अनिल कुमार पर मोटी रिश्वत

कानूनगो आलोक दुबे

लेकर झूठी रिपोर्ट लगाने का आरोप लगाया था।हालांकि, अब ग्राम प्रधान ने अपनी शिकायत अचानक वापस ले ली, जिससे पूरे प्रकरण पर नए सवाल उठ गए हैं।स्थानीय सूत्रों के अनुसार, राजस्व विभाग के कुछ प्रभावशाली अधिकारी तथा कुछ स्थानीय वर्चस्ववादी भू माफियाओं के द्वारा दबाव बनाकर शिकायत को ठंडे बस्ते में डलवाने का प्रयास किया जा रहा है।

आलोक दुबे कनेक्शन फिर आया सामने

सुरार वही क्षेत्र है, जहाँ कुछ वर्ष पहले कानूनगो आलोक दुबे तैनात थे। जिन पर फर्जी रजिस्ट्री और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों में एंटी करप्शन ब्यूरो ने चार्जशीट दाखिल की है। सूत्र बताते हैं कि सुरार की जमीनों पर कब्जे का यह नया खेल भी उसी नेटवर्क से जुड़ा हुआ है। नायब तहसीलदार रिचा सचान की जांच में आराजी 608 का कुछ हिस्सा ही सरकारी पाया गया और उसी पर बुलडोज़र चलाया गया, परंतु आराजी संख्या 308 का अधिकतम भूभाग और शेष तीन आराजियों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई।लेखपाल अनिल कुमार, जिन पर मिलीभगत के आरोप हैं, ने पहले स्वराज इंडिया की टीम से बातचीत में कब्जे से इनकार किया था जबकि अब वही भूमि सरकारी निकली है और उस पर बुलडोजर चलाकर कार्यवाही भी की गई है तो यह साबित होता है कि लेखपाल के द्वारा भू माफियाओं को समर्थन दिया गया था।

डीएम का स्पष्ट संदेश, पर फाइलों में अटकी सख्ती

जिलाधिकारी के द्वारा स्पष्ट कहा गया है कि ग्राम समाज की भूमि पर कब्जा करने वालों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। ऐसे व्यक्तियों पर मुकदमा दर्ज कर सख्त कार्रवाई की जाएगी।लेकिन, ज़मीनी हकीकत इसके उलट दिख रही है।राजस्व विभाग अब तक किसी भी भू-माफिया या भ्रष्ट लेखपाल पर मुकदमा दर्ज नहीं कर पाया है, जिससे यह सवाल उठ रहा है कि क्या अनिल कुमार को अगला 'आलोक दुबे पार्ट-2' बनने की खुली छूट दी जा रही है? सुरार प्रकरण ने एक बार फिर यह साबित किया है कि भू-माफिया और भ्रष्ट राजस्व कर्मियों की जुगलबंदी प्रशासन की साख पर सबसे बड़ा दाग बन चुकी है।

मिशन शक्ति के तहत सर्विलांस व पुलिस टीम की बड़ी कार्रवाई

लोन लेने के लालच में गाय-बकरी बिकी, ठग भागे, पुलिस ने दबोचा

पुलिस कमिश्नर के आदेश पर टीम गठित, शिल्पा फिनकैप कंपनी के चार ठग अरेस्ट

» लैपटॉप, बायोमैट्रिक मशीन, सैकड़ों दस्तावेज सोने के लॉकेट और रूपये भी हुए बरामद।

» मास्टरमाइंड रजत वर्मा पहले भी कई जिलों में ठगी का खिलाड़ी रहा।

» विशेष संवाददाता, स्वराज इंडिया न्यूज।

बिल्हौर (कानपुर)। गरीबी और लोन की आस में गाँव के लोग अपनी गाय-बकरी तक बेच बैठे, लेकिन बदले में मिला सिर्फ ठगी और धोखा।शिवराजपुर थाना क्षेत्र के भटपुरा गांव में स्थित शिल्पा फिनकैप प्राइवेट लिमिटेड नाम की फर्जी कंपनी ने बिल्हौर और शिवराजपुर क्षेत्र के करीब 71 हजार ग्रामीणों को पचास हजार से एक लाख रुपये तक का लोन दिलाने का झांसा दिया और हर व्यक्ति से चार-चार हजार रुपये रजिस्ट्रेशन फीस के रूप में वसूल कर फरार हो गईं।

बीते 10 अक्टूबर थाना समाधान पर कई महिला-पुरुषों ने पुलिस कमिश्नर से शिकायत की थी कि उनके दस्तावेज, आधार कार्ड, फोटो और बैंक पासबुक की प्रतियां लेकर कंपनी के लोगों ने बायोमैट्रिक से अंगूठा लगवाया और दस दिन में लोन आने का भरोसा दिया था। लेकिन पैसा आने के बजाय कंपनी का ऑफिस बंद हो गया और कर्मचारी गायब हो गए। शिकायत मिलते ही पुलिस कमिश्नर ने सहायक पुलिस आयुक्त बिल्हौर अमर नाथ यादव को तत्काल जांच कर खुलासा करने का निर्देश दिया। आदेश के बाद मिशन शक्ति अभियान के तहत महिलाओं की आर्थिक ठगी के इस प्रकरण पर शिवराजपुर पुलिस व सर्विलांस टीम पश्चिम जोन ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए ठग गिरोह के चारों सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों के पास से लैपटॉप, बायोमैट्रिक मशीन, सैकड़ों आधार कार्ड, भरे और खाली फार्म, मोटरसाइकिल, फर्जी नंबर प्लेट और सोने के लॉकेट बरामद किए हैं। सभी सामान उसी ठगी की रकम से खरीदे गए थे।साथ ही पुलिस ने करीब 55 हजार रूपये भी बरामद किए। पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि गिरोह गरीब और अशिक्षित इलाकों को निशाना बनाता था। पहले खुद को फील्ड ऑफिसर बताकर गाँवों में घूमते, महिलाओं को भरोसे में लेकर लोन दिलाने की बात करते और उन्हें ऑफिस बुलाते। ऑफिस में बाकायदा ब्रांच मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर और प्यून जैसे रोल बाँटे गए थे ताकि सब कुछ असली लगे।लैपटॉप पर फॉर्म भरकर बायोमैट्रिक से साइन कराए जाते और कहा जाता था कि दस दिन में पैसा खाते में आ जाएगा। कई महिलाओं ने तो इस भरोसे में अपनी गाय-बकरी तक बेच दीं, कुछ ने उधार लेकर फीस भरी, लेकिन पैसा कभी नहीं आया।

गिरफ्तार आरोपियों में रजत वर्मा निवासी सीतापुर मास्टरमाइंड बताया गया है। पुलिस रिकॉर्ड में उसके खिलाफ आगरा व अन्य जिलों में भी इसी तरह की ठगी के कई मामले दर्ज हैं। पुलिस अब गिरोह के नेटवर्क और अन्य जिलों में इनके ठिकानों की जांच कर रही है। गुरुवार को एडीसीपी वेस्ट दिनेशचंद्र त्रिपाठी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस मामले का खुलासा किया। गिरफ्तार करने वाली टीम को पुलिस कमिश्नर 25 हजार रूपये ईनाम के रूप में देंगे।

ऑफिस में बाकायदा ब्रांच मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर और प्यून जैसे रोल बाँटे गए थे ताकि सब कुछ असली लगे।

फर्जी ब्रांच मैनेजर, फील्ड ऑफिसर सभी सलाखों के पीछे

शिल्पा फिनकैप प्राइवेट लिमिटेड के फर्जी ऑफिस का संचालन करने के लिए चारों ठगों ने अलग-अलग पद बनाए थे। जितेन्द्र गौतम उर्फ राकेश गौतम पुत्र रामप्यारे लाल निवासी ग्राम सिंघौली थाना चाँदा जनपद सुल्तानपुर ब्रांच मैनेजर था। उत्तम वर्मा उर्फ संदीप शर्मा पुत्र अवधेश कुमार निवासी ग्राम पीरपुर थाना मौहली जनपद सीतापुर लोन ऑफिसर के रूप में काम करता था। शैलेश गौतम उर्फ रोहित पुत्र विरेंद्र कुमार निवासी ग्राम सुमरांवा थाना सकरन जनपद सीतापुर फील्ड ऑफिसर था। प्रदीप गौतम उर्फ संतोष पाण्डेय पुत्र रमेश कुमार निवासी ग्राम सिंघौली थाना सिंघौली जनपद सीतापुर असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर था। चारों ने भोली जनता को लूट कर फरार होने की कोशिश की, लेकिन कानून के हाथों से बच नहीं सके। अब ये चारों ठग सलाखों के पीछे हैं।

टीएससीटी जीवनदान योजना में शिक्षकों को मिला जीवन सहारा

» गंभीर रूप से बीमार शिक्षिका डॉ. मोनिका सहाय को मिली 1.50 लाख की मदद

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो।

बिल्हौर। टीचर्स सेल्फ केयर टीम (टीएससीटी) की परोपकार और सेवा भावना की श्रृंखला में एक और सराहनीय कदम उठाया गया है। टीम की जीवनदान योजना के अंतर्गत इस माह उत्तर प्रदेश के 28 शिक्षकों को गंभीर बीमारी के इलाज हेतु 23 लाख की आर्थिक सहायता प्रदान की गई है।

जिला संयोजक सुनील कुमार वर्मा ने बताया कि एस.एन. सेन बालिका महाविद्यालय, कानपुर नगर की शिक्षिका डॉ. मोनिका सहाय (किडनी ट्रांसप्लांट हेतु) को 1,50,000 की सहायता राशि टीएससीटी जीवनदान योजना के तहत प्रदान की गई।

यह राशि टीएससीटी अध्यक्ष विवेकानंद आर्य, महामंत्री सुधेश पांडे और कोषाध्यक्ष संजीव रजक द्वारा उनकी बेटी के खाते में ऑनलाइन ट्रांसफर की गई। मंडल संयोजक जितेंद्र कुमार ने बताया कि इस माह कुल 28 शिक्षकों को सहायता राशि सीधे उनके खातों में ऑनलाइन हस्तांतरित की गई है।

जिला मीडिया प्रभारी अनूप कुमार यादव ने बताया कि टीएससीटी जीवनदान योजना के अंतर्गत यदि किसी सदस्य के इलाज पर रुपए दो लाख से अधिक का खर्च आता है तो संस्था द्वारा सहयोग राशि उपलब्ध कराई जाती है ताकि शिक्षक समुदाय को आर्थिक संकट में राहत मिल सके। टीएससीटी के जिला पदाधिकारियों (सह संयोजकों) आलोक कुमार, प्रत्यूष मिश्र, अनुभव अग्रवाल, बृजेंद्र पांडे, विजय कुमार,संगीता कटियार,अंजू गुप्ता,राम कृपाल,शशिकांत, धर्मेंद्र मिश्रा, वीरेंद्र सिंह आदि ने संस्था की इस नई पहल के लिए खुशी जाहिर की। टीएससीटी की यह पहल शिक्षक समाज में मानवता, सहयोग और एकजुटता की मिसाल बनती जा रही है।

स्वदेशी केवल आर्थिक नीति नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर भारत का आधार

बोले अरुण पाठक- स्वदेशी अपनाना ही सच्ची देशभक्ति

» बिल्हौर में स्वदेशी आंदोलन पर कार्यशाला का आयोजन

» युवाओं से स्वदेशी विचारधारा को अपनाने का आह्वान

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो।

बिल्हौर (कानपुर)। बाबा रघुनंदन दास इंटर कॉलेज बिल्हौर में गुरुवार को स्वदेशी आंदोलन विषय पर एक प्रेरणादायक कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधान परिषद सदस्य अरुण पाठक ने कहा कि स्वदेशी अपनाना ही सच्ची देशभक्ति है। स्वदेशी केवल आर्थिक नीति नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर भारत का आधार है। पाठक ने अपने संबोधन में कहा कि जब हम देश में निर्मित वस्तुओं का उपयोग बढ़ाएँगे, तब न केवल देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, बल्कि युवाओं के लिए नए रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे।

उन्होंने छात्रों से आह्वान किया कि वे जीवन के हर क्षेत्र में स्वदेशी उत्पादों को प्राथमिकता दें। कार्यक्रम में गीता गुप्ता और कार्तिकेय दीक्षित ने भी विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि युवाओं में स्वदेशी विचारधारा को आगे बढ़ाने की अपार क्षमता है। उन्होंने गांधीजी के स्वदेशी सिद्धांतों की वर्तमान समय में प्रासंगिकता पर प्रकाश डाला। विद्यालय के प्रधानाचार्य ने कहा कि इस प्रकार की कार्यशालाएँ छात्रों में राष्ट्रीय चेतना और जिम्मेदारी की भावना को जागृत करती हैं। उन्होंने सभी से अपील की कि स्थानीय उत्पादों के उपयोग को जीवनशैली का हिस्सा बनाएं।

कार्यक्रम के अंत में प्रधानाचार्य ने मुख्य अतिथि सहित सभी आगंतुकों का आभार व्यक्त किया इस दौरान श्याम कटियार, एडवोकेट नितिन कटियार, ऋषि गुप्ता, अतुल शुक्ला, कार्तिकेय शंकर दीक्षित, जे.पी. कटियार, अजीत सिंह, नीरज राठौर, शशांक मिश्रा, विक्रम मिश्रा, अनुराग शुक्ला, सौरभ शर्मा, नरेंद्र प्रताप सिंह,प्रभाकर अवस्थी तनु पांडे और अंजू त्रिपाठी आदि लोग मौजूद रहे।

कार्यक्रम के उपरांत अरुण पाठक ने अपने कैम्प कार्यालय में जनसुनवाई जनता दर्शन का आयोजन किया। जिसमें उन्होंने आमजन की समस्याएँ सुनीं और उनके त्वरित निस्तारण का आश्वासन दिया।

सम्पादकीय

जन-संवाद की सुबह, फाइल-मंथन की सांझ

पहली नजर में बड़े पद की चमक-दमक का अपना सम्मोहन होता है, लेकिन हकीकत में जिम्मेदारी-जवाबदेही व विपरीत चुनौतियों में सामंजस्य बैठाना कांटों का ताज पहनने जैसा ही होता है। अंतहीन जन-अपेक्षाओं की कसौटी पर खरा उतरना उतना ही कठिन होता है। वैसे किसी सत्ता का एक साल बहुत लंबी अवधि नहीं होती। उसके आधार पर अंतिम मूल्यांकन करना भी जल्दबाजी ही कही जाएगी, लेकिन इससे किसी नेतृत्व या सरकार की दिशा-दशा को बोध तो हो जाता है। कमोबेश, यह कसौटी हरियाणा में एक साल पूरा कर रही नायब सैनी सरकार के लिये भी है। सामाजिक न्याय के समीकरण संतुलन की कवायद के क्रम में भाजपा सरकार में मुख्यमंत्री पद तक पहुंचने वाले नायब सैनी की इस पद पर ताजपोशी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल की पसंद रही है। जब नरेंद्र मोदी चंडीगढ़-हरियाणा में संगठन का दायित्व निभा रहे थे, तो सैनी उनके कार्यालय सहयोगी थे। वे विपक्षी दलों के वरिष्ठ नेताओं को सम्मान सार्वजनिक रूप से देते नजर आते हैं, लेकिन पिछले विधानसभा सत्र में मुद्दों पर विपक्षी नेताओं को आड़े हाथों लेने से भी वे नहीं चूके। वैसे तो उनके एक साल के कार्यकाल में कई चुनौतियां सामने आती-जाती रही हैं, लेकिन हाल ही में एडीजीपी वाई.पूरन कुमार व एएसआई संदीप लाठर की आत्महत्या ने सरकार के सामने असहज स्थिति व बड़ी चुनौती पेश की। हालांकि, देर से ही सही फौरी तौर पर मामले का पटाक्षेप हुआ, लेकिन इस दौरान मुख्यमंत्री ने मुद्दे की संवेदनशीलता को महसूस कर कदम बढ़ाए। एडीजीपी द्वारा आत्महत्या की खबर उन्हें जापान दौरे के दौरान मिली तो उन्होंने दौरे में शामिल उनकी पत्नी अमनीत को अधिकारियों के साथ तुरंत भारत भेजा। भारत आते ही खुद भी वे सीधे एडीजीपी के घर संवेदना व्यक्त करने पहुंचे, तो एएसआई संदीप लाठर के घर भी परिवार को संबल देने गए।बहरहाल, ट्रिपल इंजन सरकार का लाभ नायब सैनी को जरूर मिला है। कई विकास योजनाएं कायदे से सिरे चढ़ी हैं। लेकिन लाडो लक्ष्मी योजना ट्रंप कार्ड साबित हुई है। विधानसभा चुनावों में इस योजना के वायदे का छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र चुनावों की तर्ज पर हरियाणा में भी भाजपा को खासा लाभ मिला। मिले परिणामों ने तमाम कयासों को निरर्थक साबित किया। हर जरूरतमंद महिला को सरकार की तरफ से 21 सौ रुपये मिलना, उन्हें आर्थिक स्वावलंबन देना ही है। पहले चरण में बाइस लाख महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलेगा। निस्संदेह, कमजोर वर्ग के लोगों के लिये अपनी छत का सपना पूरा करना एक दुष्कर कार्य है। हरियाणा सरकार ने दस हजार से अधिक आबादी वाले महाग्रामों में गरीबों को पचास-पचास गज व छोटे गांवों में सौ-सौ गज के प्लाट उपलब्ध कराये। शहरों में ये 25 गज के रहे। वहीं प्रधानमंत्री आवास निर्माण योजना के तहत मिलने वाले ढाई-ढाई लाख रुपये ने उनके घर के सपने को हकीकत बनाया। मुख्यमंत्री नायब सैनी की खासियत लोगों के साथ सहज उपलब्धता है। उनकी सुबह कबीर कुटीर में जन संवाद से शुरू होती है और रात फाइलों के साथ खत्म होती है। जनता के लिये सहज उपलब्धता और निरंतर संवाद लोकतंत्र की अपरिहार्य शर्त होती है।

आत्मनिर्भरता से ही सुधरेगी देश की सेहत

ज्योति मल्होत्रा

भारत ने वर्ष 2030-31 तक दलहन उत्पादन को 252 लाख टन से बढ़ाकर 350 लाख टन करने का लक्ष्य तय किया है। इसके लिए 35 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि को खेती में शामिल किया जाएगा, ताकि दालों के आयात पर निर्भरता घटे और देश दलहन उत्पादन में आत्मनिर्भर बन सके।दलहन उत्पादन में आत्मनिर्भर होने के लिए वर्ष 2030-31 तक उत्पादन को 252 लाख टन से बढ़ाकर 350 लाख टन करने का लक्ष्य तय किया है। इस हेतु 35 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि दलहन उत्पादन के दायरे में लाई जाएगी। विडंबना देखिए, भारत दुनिया का सबसे बड़ा दलहन उत्पादक और उपभोक्ता देश है, लेकिन दालों की आपूर्ति आयात पर निर्भर है।

आहार में पौष्टिक तत्वों का कारक मानी जाने वाली दालें, बढ़ते दामों के कारण गरीब की शारीरिक जरूरत पूरी नहीं कर रही हैं। ये हालात मानसून के दौरान औसत से कम या ज्यादा बारिश होने से तो उत्पन्न होते ही हैं, किसान के नकदी फसलों की ओर रुख करने के कारण भी हुए हैं। यही नहीं, यह स्थिति इसलिए भी बनी, क्योंकि पूर्ववर्ती सरकार की गलत नीतियों के चलते किसान को खाद्य वस्तुओं की बजाय, ईंधन और फूलों की फसल उगाने के लिए, कृषि विभाग ने जागरूकता के अभियान चलाए। यही वजह रही कि भूमंडलीकरण के दौर में दालों की पैदावार लगातार कम होती चली गई। दाल उत्पादन का रकबा लगभग 15 हजार हेक्टेयर कम हो गया। भारत में दालों की सालाना खपत 220 से 230 लाख टन है। मंग और आपूर्ति के इस बड़े अंतर के चलते जमाखोरों और दाल के आयातक व्यापारियों को भी बार-बार करने का मौका मिल जाता है।पौष्टिक आहार देश के हरेक नागरिक के स्वस्थ जीवन से जुड़ा अहम प्रश्न है। संविधान के मूलभूत अधिकारों में भोजन का अधिकार शामिल है। चूंकि दालें प्रोटीन और पौष्टिकता का महत्वपूर्ण जरिया हैं, इसलिए इनके आयात होने के कारण इनके भाव भी बीच-बीच में बढ़ जाते हैं। इस कारण मध्यवर्गीय व्यक्ति की थाली से दाल गायब होने लगती है। चूंकि दाल व्यक्ति की सेहत से जुड़ी है और बीमारी की हालत में तो रोगी को केवल दाल-रोटी खाने की ही सलाह चिकित्सक देते हैं। वर्ष 1951 में प्रतिव्यक्ति दालों की उपलब्धता 60 ग्राम थी, जो वर्ष 2010 में घटकर 34 ग्राम रह गई। जबकि अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार यह मात्रा 80 ग्राम होनी चाहिए। दालें भारत में प्रोटीन का प्रमुख स्रोत मानी जाती हैं। लेकिन स्थानीय मांग पूरी करने के लिए दाल उत्पादन में किसान को बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तुअर दाल की फसल आठ माह में तैयार होती है। बावजूद किसान को उचित दाम नहीं मिलते हैं। गोया, किसान साल में एक फसल उगाने में रुचि कैसे लें? विदेशों में रहने वाले भारतीय भी सबसे ज्यादा तुअर की दाल खाना पसंद करते हैं। देश में सबसे अधिक चने और अरहर की खेती होती है। इनके अलावा मूंग और उड़द दालें पैदा होती हैं। देश में 10 राज्यों के किसान दालों की खेती करते हैं। इनमें सबसे अधिक उत्पादक राज्य महाराष्ट्र है। दालें मुख्य रूप से खरीफ की फसल हैं, जो वर्षा ऋतु में बोई जाती हैं। इस ऋतु में करीब 70 प्रतिशत दालों का उत्पादन होता है।केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के अनुसार दालों के तात्कालिक भाव 85.42 रुपये प्रति किलो से लेकर 112.88 रुपए प्रति किलो तक हैं। भावों में इस उछाल का कारण जमाखोरी और सट्टेबाजी के साथ आयात का कुचक्र है। टाटा, महिंद्रा, ईजी-डे और रिलायंस जैसी बड़ी कंपनियां जब से दाल के व्यापार से जुड़ी हैं, तब से ये जब चाहे तब मुनाफे के लिए दाल से खिलवाड़ करने लग जाती हैं। जब कंपनियां बड़ी तादाद में दालों का भंडारण कर लेती हैं, तो भावों में कृत्रिम उछाल आ जाता है। हालांकि केंद्र सरकार ने दालों का भंडारण सितंबर 2024 से सीमित किया हुआ है। इस कारण भाव नियंत्रण में हैं। मीडिया दाल के बढ़ते भावों को गरीब की थाली से जोड़कर उछालता है। तब सरकार दाल के आयात के लिए विवश हो जाती है।

वैश्विक चुनौतियों के बीच अंदरूनी मुद्दों पर ध्यान जरूरी

भू-राजनीतिक

ज्वाला सिंह दास

तेजी से बदलती भू-राजनीतिक परिस्थितियों के बीच भारतीय विदेश नीति की चुनौतियां बढ़ी हैं। इनमें मध्य पूर्व के कुछ देशों व अमेरिका से संबंधों में बदलाव प्रमुख हैं। पाकिस्तान से मई झड़प के बाद दोनों ओर से तल्ख बयानबाजी और...तेजी से बदलती भू-राजनीतिक परिस्थितियों के बीच भारतीय विदेश नीति की चुनौतियां बढ़ी हैं।

इनमें मध्य पूर्व के कुछ देशों व अमेरिका से संबंधों में बदलाव प्रमुख हैं। पाकिस्तान से मई झड़प के बाद दोनों ओर से तल्ख बयानबाजी और धमकियां जारी हैं। लेकिन देश के सीमावर्ती राज्यों में तनाव ज्यादा चिंताजनक है। वहां मूल समस्याओं का हल जरूरी है।भू-राजनीतिक सत्ता के खेल के पहलू सामान्य से कहीं ज़्यादा तेजी से चल रहे हैं, और मैं खुद को हम पर पड़ने वाले प्रभाव पर आत्मचिंतन करता पा रहा हूं। हमास-इस्राइल संघर्ष मामले में शुरुआत हो चुकी है, और युद्धविराम हो गया है; इस्राइली बंधकों और फ़लस्तीनी कैदियों की अदला-बदली हुई है। इस लड़ाई से अमेरिका, ब्रिटेन, इस्राइल, मिस्र, लेबनान, यमन, ईरान, कतर, सीरिया के अलावा कुछ अन्य देश भी जुड़े थे, हो सकता है जिन्हें मैं नज़रअंदाज़ कर गया।शांति सदा स्वागत योग्य है, लेकिन बड़ा सवाल है कि क्या यह स्थायी हो पाएगी। सही तरह अमेरिका की मदद प्राप्त इस्राइल ने इस लड़ाई में अपना वर्चस्व स्पष्टतया प्रदर्शित किया है। यह भी दिखाया कि इस्राइल की अति-दक्षिणपंथी विचारधारा में फ़लस्तीनी राज्य के विचार के प्रति ज़ीरो टॉलरेंस है, और

फिलहाल यही नीति हावी है। यह गाज़ा पर बमबारी, वैस्ट बैंक पर बसने वालों को दिए समर्थन और तमाम विरोध कठोरता से कुचलने में देखने को मिला। क्या इससे फ़लस्तीनी देश और द्वि-राष्ट्र समाधान की मांग समाप्त हो जाएगी...शायद नहीं।अंततः, यह तीन प्राचीन समुदायों और धर्मों के बीच की सांप्रदायिक रार है। यरुशलम को लेकर सदियों से लड़ाई जारी है... यहीं से ईसाई धर्म, इस्लाम और यहूदी धर्म की उत्पत्ति हुई, और यह मान बैठना ज्यादा ही सरल होगा कि अब सब झगड़ा सुलझ गया है। मध्य पूर्व के विशाल कच्चे तेल भंडारों पर नियंत्रण की इच्छा भी महाशक्तियों के लिए हस्तक्षेप करने में बड़ा लालच है। यह देखते हुए कि यूरोप के अधिकांश देशों और ब्रिटेन ने हाल ही में फ़लस्तीनी राज्य को मान्यता दी है, हमास को निरस्त्र करने और फ़लस्तीनी समस्या के समाधान की मांगों पर अभी बहुत काम करना बाकी है।क्या इस संघर्ष में हमारी स्थिति ने मध्य पूर्व के उन देशों के साथ संबंधों में शायद कुछ ठंडक ला दी है, जिनके साथ अतीत में हमारे रिश्ते मधुर रहे हैं? पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच हालिया रक्षा समझौता इसका संकेत देता है। इसके अलावा, अमेरिका और पाकिस्तान के बीच फिर से बना दोस्ताना भी हमारे लिए चिंता बढ़ाने वाला है। अमेरिका को ईरान, अफ़ग़ानिस्तान और चीन के नज़दीक एक रणनीतिक साझेदार चाहिये...और पाकिस्तान की सीमा इन तीनों से लगती है। वहीं खुफ़िया जानकारी और रसद सहायता प्रदान करने में भी वह उपयोगी है।

पाकिस्तान की सभी पक्षों के साथ खेलने की चाह का असर अफ़ग़ानिस्तान के साथ लगती उसकी उत्तरी सीमाओं पर पहले ही पड़ रहा है, जहां झड़पें और हताहतों की संख्या बढ़ रही है। पाकिस्तानी एक ही वक्त चीन और अमेरिका के साथ संबंधों के संतुलन को कैसे साध पाएगा, यह एक कूटनीतिक कौतुक होगा।यह परिस्थिति हमारी सुरक्षा के लिए सवाल पैदा करती है कि क्या अमेरिका और चीन, पाकिस्तान को लुभाने की खातिर, कश्मीर के बारे उसकी आसक्ति में साथ देंगे? क्या इस क्षेत्र में संघर्ष बड़ी ताकतों को माफिक होगा? दशकों से, हमारी नियंत्रण रेखा सक्रिय रही है, जिस पर पूर्ण युद्ध से लेकर बमबारी और सीमित झड़पों तक, विभिन्न स्तर के टकराव होते आए हैं।

कानपुर नगर निगम मुख्यालय में वेलिंगबरो (इंग्लैंड) के मेयर का भव्य स्वागत

महापौर प्रमिला पांडेय सहित पार्षदों ने किया अभिनंदन, गुब्बारों और कालीनों से सजा नगर निगम भवन

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर। नगर निगम मुख्यालय मोतीझील में एक विशेष अवसर देखने को मिला, जब वेलिंगबरो (इंग्लैंड) के मेयर राज मिश्रा का नगर निगम परिवार की ओर से भव्य स्वागत किया गया। महापौर प्रमिला पांडेय के नेतृत्व में नगर निगम मुख्यालय को आकर्षक ढंग से गुब्बारों, पुष्पों और लाल कालीन से सजाया गया था। पूरा परिसर स्वागत की उमंग से सराबोर नजर आया।

मेयर राज मिश्रा के स्वागत समारोह में नगर आयुक्त अर्पित उपाध्याय, पवन पाण्डेय, पार्षद सौरभ देव, नीरज रक्सेल, नीरज कुमार गुप्ता, आरती त्रिपाठी, विकास साहू, डॉ. अखिलेश वाजपेयी, वीरेन्द्र सिंह, कौशल कुमार मिश्रा, नीरज सिंह, आनन्द शुक्ला और राम नारायण सहित अनेक गणमान्य जन उपस्थित रहे।

स्वागत समारोह के दौरान दोनों नगरों के बीच सहयोग, संस्कृति और विकास के अनुभव साझा करने पर चर्चा हुई। इस अवसर पर महापौर ने कहा कि यह हमारे लिए गर्व की बात है कि वेलिंगबरो जैसे ऐतिहासिक नगर के मेयर आज हमारे बीच हैं। इस मुलाकात से दोनों शहरों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध और मजबूत होंगे।

कार्यक्रम के अंत में मेयर राज मिश्रा ने नगर निगम टीम के आतिथ्य की सराहना करते हुए कहा कि कानपुर की गर्मजोशी और परंपरागत आतिथ्य भाव अविस्मरणीय है।

जुए की फड़ पर क्राइम ब्रांच का छापा, 19 गिरफ्तार

» प्रमुख संवाददाता स्वराज इंडिया

» क्राइम ब्रांच ने मकान में चल रहे हाई-प्रोफाइल जुए का किया भंडाफोड़

» थाना पुलिस अनजान, क्राइम ब्रांच ने पकड़े जुआड़ी और थाने को सौंपे

कानपुर। कानपुर कमिश्नरेट में पुलिस आयुक्त रघुवीर लाल के निर्देश पर क्राइम ब्रांच की टीम ने गुरुवार रात किदवई नगर थाना क्षेत्र के साइड नंबर-1 इलाके में बड़ी कार्रवाई की। टीम ने एक मकान में चल रही लाखों की जुए की फड़ पर छापा मारते हुए 19 जुआड़ियों को मौके से गिरफ्तार किया।छापेमारी के दौरान पुलिस को करीब 7.5 लाख नकद, ताश के पत्ते और अन्य जुए से संबंधित सामग्री बरामद हुई।

यह कार्रवाई सीपी रघुवीर लाल के विशेष अभियान के तहत की गई, जिसमें अपराध और अवैध गतिविधियों पर सख्त रोक लगाने के निर्देश दिए गए हैं।प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, जिस मकान में यह फड़ चल रही थी, वहां रोजाना देर रात तक जुआ खेला जाता था। आश्चर्य की बात यह रही कि स्थानीय थाना पुलिस को इस अवैध गतिविधि की भनक तक नहीं लगी। कार्रवाई के बाद क्राइम ब्रांच ने सभी आरोपितों को किदवई नगर थाना पुलिस के सुपुर्द कर दिया है।सूत्रों के मुताबिक, गिरफ्तार जुआडियों में कई कारोबारी और बाहरी जनपदों के लोग भी शामिल हैं। फिलहाल पुलिस सभी से पूछताछ कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश में है कि इस फड़ के पीछे कौन बड़ा संचालक है। पुलिस कमिश्नरेट सूत्रों का कहना है कि यह कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी और अवैध जुए, सट्टे और नशे के कारोबार में लिप्त लोगों पर शिकंजा कसेगा।

सेठ आनंदराम जैपुरिया स्कूल में 'हाट से हार्ट तक - 2025' का आयोजन

» विशेष दिव्यांग बच्चों की प्रतिभा को मिला नया मंच

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर। सेठ आनंदराम जैपुरिया स्कूल, कानपुर में आज 'हाट से हार्ट तक - 2025' शीर्षक से एक मनोरंजक एवं प्रेरणादायी मेले का आयोजन किया गया। इस विशेष कार्यक्रम का उद्देश्य दिव्यांग बच्चों में आत्मविश्वास, स्वावलंबन और सामाजिक समावेश की भावना को प्रोत्साहित करना था।

मेले में संजीवनी कानपुर प्लॉगर्स, संकल्प शेल्टर वर्कशॉप, अमृता रिहेबिलिटेशन सेंटर और आशाएं स्पेशल स्कूल जैसी संस्थाओं ने सक्रिय भागीदारी की। दिव्यांग विद्यार्थियों द्वारा निर्मित हस्तनिर्मित सजावटी वस्तुएँ, आकर्षक क्राफ्ट आइटम और स्वादिष्ट व्यंजन प्रदर्शनी एवं बिक्री के लिए रखे गए थे। विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों ने उत्साहपूर्वक खरीदारी कर इन विशेष बच्चों का मनोबल बढ़ाया।

यह आयोजन केवल मनोरंजन तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसने करुणा, सहानुभूति और सामाजिक संवेदनशीलता जैसे मानवीय मूल्यों को भी सशक्त किया।

विद्यार्थियों को रचनात्मकता और सामाजिक उत्तरदायित्व के साथ जुड़ने का अवसर मिला।

विद्यालय के प्रधानाचार्य गणेश तिवारी ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे आयोजन विशेष दिव्यांग विद्यार्थियों को सशक्त बनाते हैं और उन्हें समाज की मुख्यधारा से जोड़ते हैं।

ये कार्यक्रम विद्यालय में सकारात्मकता और परस्पर सहयोग की भावना को प्रोत्साहित करते हैं।

कार्यक्रम में विद्यालय के सभी छात्र-छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और 'हाट से हार्ट तक' के माध्यम से मानवीय संवेदना और सामाजिक एकता का सुंदर संदेश दिया।

गरीबों और बुजुर्गों के बीच मनाया समाजसेवी शिवम यादव का जन्मदिन

विष्णु फाउंडेशन की अगुवाई में अपना घर वृद्ध आश्रम में हुआ कार्यक्रम

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर। समाजसेवा की मिसाल पेश करते हुए भीतरगांव ब्लॉक निवासी एवं भारतीय नेवी में कार्यरत समाजसेवी शिवम यादव ने अपना जन्मदिन गरीबों और बुजुर्गों के साथ अपना घर वृद्ध आश्रम में मनाया। श्री विष्णु फाउंडेशन के तत्वावधान में आयोजित इस विशेष अवसर पर आश्रम में गुब्बारे, फूलों और दीपों से सजावट की गई थी।

कार्यक्रम के दौरान शिवम यादव ने वृद्धजनों के साथ समय बिताया, उनका हालचाल जाना और दोपहर का भोजन साझा किया। उन्होंने बताया कि—ञ्जन्मदिन तो हर कोई दोस्तों और परिवार के साथ मना लेता है, लेकिन जो सच्ची खुशी बुजुर्गों और असहायों के बीच मिली, वह अनमोल है। शिवम यादव ने अपने क्षेत्र के लोगों से भी अपील की कि वे अपने विशेष अवसरों—जन्मदिन, वर्षगांठ या अन्य पर्वों पर—गरीबों, अनाथों और बुजुर्गों के साथ समय बिताएं और उनकी सहायता करें।इस अवसर पर उनकी टीम द्वारा लगभग 600 लोगों को भोजन कराया गया तथा जरूरतमंदों को फल और खाद्य सामग्री वितरित की गई।

कार्यक्रम में श्री विष्णु फाउंडेशन के सचिव सत्यम विष्णु अवस्थी, आश्रम प्रेसिडेंट उमा शुक्ला, सचिव जे.पी. सिंह, प्रधान शिवेंद्र मिश्रा, शिक्षक अरविन्द यादव, विकास यादव, सत्यम यादव, कृष्णा, अनुज और प्रिंस सहित अनेक लोग उपस्थित रहे।

फाइल में चल रही सरकारी योजनाएं धरातल की हकीकत कुछ और

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर देहात। शासन के निर्देश पर जनपद में करोड़ों रुपए खर्च कर दर्जन भर ग्राम पंचायत में नवीन अंत्येष्टि स्थल निर्माण कार्य हो चुका है , लेकिन मलासा ब्लॉक के मावर गांव में बना स्थल का प्रयोग न किए जाने से दोनो जगह तीन शेड टूट कर अंत्येष्टि स्थल पूरी तरह से बदहाल हो गया है। अंत्येष्टि स्थल गिर रहे है।

» अंत्योष्टि स्थल हो गया जर्जर, ग्राम पंचायत सचिव और ग्राम प्रधान बने अनजान

परिसर पर बड़ी-बड़ी घास जम गई है। अंत्येष्टि स्थल पहुंचने के लिए रास्ता भी खराब है। लेकिन जिम्मेदार अधिकारी सब कुछ जानते हुए भी अंजान बने हुए हैं।

सरकार द्वारा नदियों को सुरक्षित करने के लिए शव बहाने पर लगी रोक के बाद अंत्येष्टि स्थलों का निर्माण कर कराया गया था लेकिन पूर्व में बने अंत्येष्टि स्थलों का प्रयोग में नहीं लेने से लाखों रुपए की लागत से बने अंत्येष्टि स्थल बदहाली का शिकार है। अंत्येष्टि स्थल की दीवार भी टूट गई है लेकिन जिम्मेदार अफसर ध्यान नहीं दे रहे हैं।

धरातल पर सरकारी योजनाएं दम तोड़ रही हैं। अंत्येष्टि स्थल पूरी तरह से बदहाल हो चुका है।

वहां शौचालय की हालत खराब और ताला लगा हुआ है। जब से बना

आज तक इसकी कोई मरम्मत का कार्य नहीं कराया गया है। जिससे पूरी तरह से जर्जर हो रहा है। पंचायत विभाग सिर्फ कागजों पर ही इस अंत्येष्टि स्थल संचालन दिखा रहे है। जबकि जमीनी हकीकत के प्रति पंचायत के जिम्मेदार सचिव और प्रधान संवेदनहीन रवैया सामने आया है।

क्या बोले जिम्मेदार अधिकारी

इस प्रकरण को लेकर मलासा ब्लॉक के खंड विकास अधिकारी संजय सिंह कनौजिया ने कहा है कि मामले की जानकारी आपके द्वारा मिली है अभी उसका निरीक्षण किया जा रहा है जल्द ही इसकी मरम्मत करके संचालित कराया जाएगा और लापरवाही बरतने वाले सचिवों में कार्यवाही होगी।

दीपावली पर एक कॉल पर उपलब्ध होगी 108 एंबुलेंस सेवा

108 एवं 102 एंबुलेंस में जीवन रक्षक दवाओं के साथ इमरजेंसी सुविधाएं व प्रशिक्षित स्टाफ होगा

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर देहात। दिवाली के मौके पर 108 एवं 102 एम्बुलेंस सेवाएं एक कॉल पर उपलब्ध रहेंगी। एम्बुलेंस सेवा प्रदाता संस्था ने सभी एम्बुलेंसों को 24 घंटे अलर्ट रहने और आवश्यक्ता पड़ने पर जल्द से जल्द मरीज को सेवा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश के सभी जिलों में 108 एम्बुलेंस 24 घंटे लोगों की सेवा के लिए उपलब्ध रहेंगी। कोई भी व्यक्ति 108 नम्बर पर कॉल करके एम्बुलेंस सेवा का लाभ ले सकता है।

उत्तर प्रदेश में 108 एवं 102 एम्बुलेंस सेवा प्रदाता संस्था ईएमआईआरआई ग्रीन हेल्थ सर्विसेज के प्रोग्राम मैनेजर प्रदीप पाठक ने बताया कि दिवाली पर 108 सेवा की सभी 24 एंबुलेंस मरीजों की सेवा के लिए 24 घंटे तैयार रहने का अलर्ट जारी किया गया है। सभी एंबुलेंसों में आवश्यक दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित रखने के निर्देश दिए गए हैं। 108 एंबुलेंस चिन्हित किए गए विशेष स्थानों, दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्रों व थानों के नजदीक मौजूद रहेगी। सभी एंबुलेंसों में जीवन रक्षक दवाओं के साथ इमरजेंसी सुविधाएं व प्रशिक्षित स्टाफ उपलब्ध है।

जलने पर क्या करें

दिवाली पर पटाखों से या दीयों से जलने की दुर्घटनाएं होने का खतरा रहता है। इसलिए दिवाली पर ढीले कपड़े पहनने से बचें। ईएमआरआई ग्रीन हेल्थ सर्विसेज के ईएमएलसी हेड डॉ. दाउद हुसामी ने बताया कि पटाखे छुड़ाने के दौरान पानी नजदीक में रखें। पटाखों से जलने या अन्य कारण से जलने की स्थिति में जले हुए अंग पर सादा पानी या नल का पानी लगातार 15 मिनट तक डालें। घाव को साफ रखें। कोई पट्टी या कपड़ा ना बांधे, किसी साफ कपड़े से जले हुए अंग को कवर करें। जले हुए अंग पर टूथपेस्ट, हल्दी, नमक, या अन्य किसी भी वस्तु का लेप न करें। तुरंत एम्बुलेंस को कॉल करें और अस्पताल पहुंचकर डॉक्टर को दिखाएं।

खेत पर गिरी हाईटेंशन लाइन, गन्ने की फसल खाक

» ग्रामीणों ने पानी डालकर बुझाई आग, किसान को लाखों का नुकसान

नुकसान का जायजा लेने पहुंचे लेखपाल

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर देहात। ग्राम पंचायत गजनेर में शुक्रवार दोपहर बिजली विभाग की लापरवाही एक किसान के लिए भारी पड़ गई। खेत के ऊपर से गुजर रही हाईटेंशन लाइन का तार टूटकर गिर गया। जिससे रहीम पुत्र मुंशी की करीब पांच बीघा में खड़ी गन्ने की फसल आग की चपेट में आकर जलकर राख हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, दोपहर करीब एक बजे अचानक जोरदार चिंगारी के साथ तार खेत में गिरा और देखते ही देखते पूरी फसल धधक उठी। आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक फसल राख में बदल चुकी थी। रहीम ने बताया कि उसने कई बार बिजली विभाग को खराब तारों और ढीले पोलों की सूचना दी थी, लेकिन विभागीय अधिकारियों ने कोई कार्रवाई नहीं की।

उसका कहना है कि इस हादसे में उसे करीब तीन लाख रुपये का नुकसान हुआ है। सूचना पर लेखपाल मौके पर पहुंचे और नुकसान का मुआयना किया। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि क्षेत्र में जर्जर बिजली तारों के चलते आए दिन ऐसे हादसे हो रहे हैं, लेकिन विभाग सिर्फ हादसे के बाद औपचारिकता निभाने तक सीमित रहता है। उन्होंने प्रशासन से पीड़ित किसान को उचित मुआवजा दिलाने और बिजली विभाग के जिम्मेदार अफसरों पर कार्रवाई की मांग की है।

स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक सपना देवी द्वारा हर्षिता प्रिंटर्स 127/875, साकेत नगर, कानपुर नगर- (उ़प्र) से मुद्रित व 119/13, दर्शनपुरवा, कानपुर नगर- 208012 (उ़प्र) से प्रकाशित। संपादकः अनूप कुमार **RNI No.:** UPHIN/2023/86769 | **Email:** swarajindia2023@gmail.com | **Mob:** 7800009853, | **Website:** www.swarajindianews.com | (समस्त वाद-विवाद कानपुर न्यायालय के अधीन होंगे)

धनतेरस-दीपावली पर जाम से निपटने की तैयारी, बिरहाना रोड,गोविंदनगर और कल्याणपुर का कल से डावर्जन

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर। धनतेरस-दीपावली को देखते हुए कानपुर में 18, 19 और 20 अक्तूबर को बिरहाना रोड, गोविंदनगर और कल्याणपुर समेत कई मुख्य मार्गों पर दोपहर एक बजे से रात 12 बजे तक यातायात डायवर्जन लागू रहेगा। पुलिस ने जाम से बचने के लिए प्लान जारी किया है और पार्किंग व्यवस्था निर्धारित की है।कानपुर शहर के बाजारों में धनतेरस और दीपावली की खरीदारी के लिए शनिवार से भीड़ उमड़ेगी।

यहां जाम न लगे इसके लिए ट्रैफिक विभाग की ओर से कई जगह डायवर्जन लागू किया जा रहा है। इसके तहत बिरहाना रोड, फूलबाग, हटिया, नयागंज, गोविंदनगर, कल्याणपुर–पनकी रोड में 18, 19 और 20 अक्तूबर को दोपहर एक से रात 12 बजे तक यातायात व्यवस्था लागू रहेगी। इसी के चलते डीसीपी ट्रैफिक रविंद्र कुमार, एडीसीपी ट्रैफिक अर्चना सिंह, एसीपी कलक्टरगंज आशुतोष सिंह, बादशाहीनाका, मूलगंज, कलक्टरगंज थाना प्रभारियों ने गुरुवार को बाजार का निरीक्षण किया। यहां अतिक्रमण हटवाया।

डायवर्जन प्लान

फूलबाग चौराहे से सराफा बाजार जाने वाले वाहन ही बिरहाना रोड की तरफ जाएंगे। बिरहाना रोड में वाहन खड़े नहीं होंगे।

बिरहाना रोड के सराफा बाजार में भीड़–भाड़ व वाहनों का अधिक दबाव होने पर फूलबाग चौराहा से बिरहाना रोड की तरफ वाहन नहीं जा सकेंगे।

घंटाघर चौराहे से वाहन नयागंज और दवा मार्केट होते हुए बिरहाना रोड की तरफ नहीं जाएंगे। उन्हें नरोना चौराहा से फूलबाग चौराहा होकर बिरहाना रोड भेजा जाएगा।

नयागंज दवा मार्केट के स्थानीय वाहन जिन्हें सिरकी मोहाल होते हुए बिरहाना रोड की तरफ जाना है, उन्हें सिरकी मोहाल चौकी चौराहा से एक्सप्रेस रोड नरोना के लिए रवाना किया जाएगा।

बड़ा चौराहा पर जाम लगने पर मेघदूत तिराहे से दो पहिया के अलावा अन्य वाहन बड़ा चौराहा नहीं जा सकेंगे। उन्हें मेघदूत तिराहा से वीआईपी रोड होते हुए भेजा जाएगा।

कोतवाली चौराहे से वाहन मूलगंज की तरफ नहीं जा सकेंगे। उन्हें वाहन क्रिस्टल पार्किंग में खड़े करने पड़ेंगे।

रामबाग चौराहे से पीरोड के लिए वाहन नहीं जा सकेंगे। उन्हें रामबाग चौराहे से दाएं मुड़कर ब्रह्मनगर चौराहे से जाने की अनुमति रहेगी।

जरीबचौकी चौराहा से वाहन पीरोड की तरफ नहीं जा सकेंगे। उन्हें टेनरी चौराहा से उनके गंतव्य के लिए भेजा जाएगा।

कल्याणपुर क्रॉसिंग से वाहन पनकी की तरफ नहीं जा सकेंगे। उन्हें गूबा गार्डन से बाएं मुड़कर आगे के लिए रवाना किया जाएगा।

सीएनजी पेट्रोल पंप से वाहन कल्याणपुर क्रॉसिंग की तरफ नहीं जा सकेंगे। उन्हें पंप से दाएं मुड़कर बगिया क्रॉसिंग से आगे भेजा जाएगा।

पनकी नहर से बड़े वाहन कल्याणपुर क्रॉसिंग की तरफ नहीं जा सकेंगे।

चावला चौराहा से चार पहिया वाहन गोविंदनगर मार्केट की तरफ नहीं जा पाएंगे।

सीटीआई तिराहे से वाहन गोविंदनगर मार्केट की तरफ नहीं जा सकेंगे।

भोला डेयरी से वाहन गोविंदनगर मार्केट की तरफ नहीं जा पाएंगे।

कूड़े के ढेर में लगी आग

नगर पंचायत की लापरवाही ने बढ़ाया प्रदूषण

खुले में जलाया जा रहा कूड़ा बना लोगों की परेशानी, ईओ ने कर्मचारियों पर कार्रवाई के दिए निर्देश

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर देहात। केंद्र सरकार के 'स्वच्छ भारत मिशन' पर करोड़ों रुपये खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन रसूलाबाद नगर पंचायत क्षेत्र में हालात इसके विपरीत हैं। गुरुवार को बिल्हौर रोड स्थित वन कॉलोनी के पास खुले में डंप किए गए कूड़े के ढेर में आग लग गई। कुछ ही देर में धुआं पूरे इलाके में फैल गया, जिससे दृश्यता कम हो गई और वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। स्थानीय लोगों ने बताया कि नगर पंचायत की ओर से कूड़ा खुले में फेंका जाता है और कई बार कर्मचारियों द्वारा उसे जला भी दिया जाता है।

इससे लगातार वायु प्रदूषण बढ़ रहा है और आसपास के लोगों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है।

ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि जब किसानों के पराली जलाने पर जुर्माना लगाया जाता है, तो नगर पंचायत के इस खुलेआम कूड़ा जलाने पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती? इस मामले पर अधिशासी अधिकारी कुलकमल सिंह ने बताया कि सूचना मिलते ही कर्मचारियों को मौके पर भेजा गया। आग बुझाने और सफाई कराने के निर्देश दिए गए हैं।

साथ ही, लापरवाही बरतने वाले कर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही है। स्थानीय नागरिकों ने शासन से नगर पंचायत की कार्यप्रणाली की जांच कर जिम्मेदारों को दंडित करने की मांग की है, ताकि 'स्वच्छ भारत मिशन' का असली उद्देश्य धरातल पर उतर सके।

नशे में धुत तीमारदार ने डॉक्टर से की अभद्रता, इमरजेंसी सेवा बाधित

अयोध्या जिला अस्पताल में फिर हंगामा

» डॉ. वीरेंद्र वर्मा की तहरीर पर पुलिस जांच शुरू, सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल

»स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

अयोध्या। जिला अस्पताल में गुरुवार देर रात फिर हंगामा हो गया। नशे में धुत तीमारदारों ने गाली-गलौज और डॉक्टरों के साथ अभद्रता की। यह घटना उस वक्त हुई जब इमरजेंसी वार्ड पहले से ही मरीजों से भरा हुआ था और ड्यूटी पर मौजूद चिकित्सक लगातार दबाव में काम कर रहे थे। डाक्टर ने पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई के लिए कहा है।

ईएमओ डॉ. वीरेंद्र वर्मा के मुताबिक, रात करीब सवा दस बजे शिव नगर निवासी अशोक कुमार को चोटिल अवस्था में अस्पताल लाया गया। मरीज शराब के नशे में था और उसके साथ आया पड़ोसी जो बैटरी रिक्शा चालक बताया जा रहा है खुद भी नशे में था। इलाज शुरू होते ही वह डॉक्टर से बहस करने लगा, फिर गाली गलौज और हाथापाई की नौबत तक पहुंच गया। डॉ. वर्मा का कहना है, अस्पताल में पहले से ही चिकित्सकों की भारी कमी है। इमरजेंसी में 20-25 मरीज एक साथ आ जाते हैं। ऐसे में अगर तीमारदार ही हंगामा करने लगें, तो बाकी मरीजों का इलाज रुक जाता है। इस घटना के बाद डॉक्टर ने नगर कोतवाली में लिखित शिकायत देकर दोषी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। अस्पताल प्रशासन ने भी इसे गंभीर माना है और कहा है कि ड्यूटी पर तैनात डॉक्टरों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। अस्पताल के वरिष्ठ कर्मियों का कहना है कि ऐसे प्रकरण अब आम होते जा रहे हैं। नशे में आए तीमारदारों की बदतमीजी से डॉक्टरों का मनोबल गिर रहा है, और कई बार मरीजों की जान पर असर पड़ता है।

संगठन या स्वार्थ का संघ?

अद्भुत विडंबना है सिर्फ दो दिन पहले गठित हुआ जिला अस्पताल संयुक्त कर्मचारी संगठन, जिसने कर्मचारियों की आवाज़ बनने का दावा किया था, वही संघठन इस घटना पर एक निंदा प्रस्ताव तक जारी नहीं कर सका! नशे में धुत व्यक्ति डॉक्टर से अभद्रता करता है। सरकारी कार्य में बाधा डालता है, मगर संगठन की जुबान बंद रही। अब सवाल यही उठता है क्या यह संघठन कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए बना है, या फिर सिर्फ कुर्सी और व्यक्तिगत लाभ की राजनीति के लिए?

स्मार्ट प्रीपेड मीटर और 6 गुना महंगी कनेक्शन दरों से उपभोक्ता नाराज़

» उत्तर प्रदेश में नए बिजली कनेक्शन पर स्मार्ट प्रीपेड मीटर अनिवार्य करने और दरों में 6 गुना वृद्धि से उपभोक्ताओं में आक्रोश

»दीपावली के अवसर पर पावर कारपोरेशन के निर्णय के खिलाफ उपभोक्ता परिषद ने उठाई आवाज, सरकार से तत्काल हस्तक्षेप की मांग

»स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

लखनऊ/कानपुर। दीपावली के अवसर पर प्रदेश में नए बिजली कनेक्शन की दरों में छह गुना तक वृद्धि और उपभोक्ताओं के घरों में अनिवार्य रूप से स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जाने के निर्णय से पूरे प्रदेश में विद्युत उपभोक्ताओं में भारी आक्रोश है। उपभोक्ता परिषद इस गंभीर मामले को लेकर सरकार के पास पहुंची और तत्काल हस्तक्षेप की मांग की।

उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने सचिवालय में अपर मुख्य सचिव (ऊर्जा) नरेंद्र भूषण से मुलाकात कर लंबी चर्चा की। उन्होंने बताया कि पावर कारपोरेशन का यह निर्णय विद्युत अधिनियम 2003 का उल्लंघन है और इससे प्रदेश की जनता को 'लालटेन युग' में ले जाने की साजिश की जा रही है।

परिषद अध्यक्ष ने कहा कि कॉरपोरेशन के अध्यक्ष स्वयं यह स्वीकार कर चुके हैं कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर की मौजूदा कीमत 6016 रुपये है, जबकि 8000 रुपये से अधिक कीमत का प्रस्ताव नियामक आयोग को भेजा गया है। इसका अर्थ यह है कि भविष्य में नए कनेक्शन की लागत 9000 रुपये तक पहुंच सकती है।

उपभोक्ता परिषद का आरोप है कि पावर कारपोरेशन केंद्र सरकार की आरडीएसएस योजना के साथ भी बड़ा खेल कर रहा है। इस योजना के तहत उपभोक्ताओं के घरों में मुफ्त में बदले जाने वाले स्मार्ट प्रीपेड मीटर को नए कनेक्शन पर लगाकर उनसे भारी रकम वसूली जा रही है। इससे न केवल उपभोक्ताओं का आर्थिक शोषण हो रहा है बल्कि केंद्र सरकार की छवि भी धूमिल की जा रही है।

परिषद की ओर से अपर मुख्य सचिव (ऊर्जा) को एक विस्तृत वैधानिक प्रपत्र सौंपा गया, जिसमें इस पूरी प्रक्रिया की अनियमितताओं का ब्यौरा दिया गया है।

बताया गया कि बिना नियामक आयोग की अनुमति के कनेक्शन दरों में 1032 रुपये से बढ़ाकर 6176 और 6400 रुपये तक की वृद्धि की गई है। साथ ही उपभोक्ताओं को पोस्टपेड और प्रीपेड मीटर के विकल्प से भी वंचित कर दिया गया है, जो विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 47(5) का उल्लंघन है।

अवधेश वर्मा ने कहा कि अपर मुख्य सचिव (ऊर्जा) से हुई बातचीत सौहार्दपूर्ण रही और उन्होंने परिषद के प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार करने का आश्वासन दिया है। उधर, विद्युत नियामक आयोग ने भी परिषद के प्रस्ताव पर विचार शुरू कर दिया है।

उपभोक्ता परिषद ने कहा है कि दीपावली जैसे प्रकाश पर्व पर इस प्रकार का मनमाना और असंवैधानिक आदेश प्रदेश की जनता के साथ धोखा है तथा सरकार की छवि को नुकसान पहुंचाने वाला कदम है। परिषद ने स्पष्ट किया है कि वह इस मुद्दे पर जल्द ही मुख्यमंत्री, ऊर्जा मंत्री और राज्यपाल से भी मुलाकात करेगी ताकि उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा की जा सके।

नगर निकाय कर्मचारियों और सरकार के बीच टकराव बढ़ेगा

माँगों पर संतोषजनक निर्णय न होने से महासंघ ने 17 अक्टूबर से क्रमिक अनशन और आंदोलन का किया ऐलान

»स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

लखनऊ।उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ की लम्बित माँगों को लेकर सरकार और कर्मचारियों के बीच टकराव गहराता जा रहा है। 9 अक्टूबर को हुए विशाल धरना-प्रदर्शन और ज्ञापन प्रेषण के बाद गुरुवार को विशेष सचिव नगर विकास श्री सत्य प्रकाश पटेल की अध्यक्षता में महासंघ के प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित की गई।

बैठक में 10 सूत्रीय मांग पत्र में से दो प्रमुख मुद्दों अकेंद्रीकृत कर्मचारियों की सेवा नियमावली तथा 31 दिसम्बर 2001 तक दैनिक वेतन, संविदा एवं तदर्थ (धारा 108) पर कार्यरत कर्मचारियों के विनियमितीकरण – पर विस्तृत चर्चा हुई। बैठक के दौरान सेवा नियमावली बनाने हेतु समिति गठन एवं विनियमितीकरण पर आवश्यक जानकारी तत्काल निदेशालय की ईमेल आईडी पर भेजने के निर्देश जारी किए गए। हालांकि शेष माँगों पर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया जा सका, जिससे कर्मचारी नेताओं में नाराज़गी देखी गई।असंतोषजनक परिणाम के चलते महासंघ ने अपने पूर्व घोषित आंदोलन को जारी रखते हुए 17 अक्टूबर से 10 नवम्बर तक क्रमिक अनशन करने का निर्णय लिया है। इस दौरान प्रदेश की सभी इकाइयों के कम से कम पाँच प्रतिनिधि प्रतिदिन लखनऊ नगर निगम मुख्यालय पर दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक अनशन पर बैठेंगे। साथ ही सभी निकाय कर्मचारी इस अवधि में काला फीता बाँधकर विरोध जताएँगे। महासंघ ने यह भी घोषणा की है कि इस वर्ष दीपावली पर्व सामूहिक रूप से नहीं मनाया जाएगा।महासंघ ने प्रमुख सचिव नगर विकास को पुनः पत्र भेजकर मुख्यमंत्री एवं नगर विकास मंत्री से हस्तक्षेप की मांग की है ताकि कर्मचारियों की लम्बित सेवा सम्बन्धी समस्याओं का शीघ्र समाधान हो सके। महासंघ ने चेतावनी दी है कि यदि माँगों का निस्तारण शीघ्र नहीं हुआ तो प्रदेशव्यापी कार्यबंदी की जाएगी, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी सरकार और नगर विकास विभाग की होगी।बैठक में महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष शशि कुमार मिश्र, महामंत्री रमाकांत मिश्र, वरिष्ठ उपाध्यक्ष विनय बाघमार, सय्यद कैसर रज़ा, अवध क्षेत्र अध्यक्ष राम कुमार रावत, तथा अपर निदेशक स्थानीय निकाय ऋतु सुहास सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

गैंगरेप के आरोपी सपा नेता मोईद अहमद को मिली जमानत

अयोध्या के भदरसा सामूहिक दुष्कर्म केस में आया नया मोड़

» हाईकोर्ट से आरोपी को मिली राहत पर पीड़ित पक्ष ने उठाए सवाल

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

अयोध्या। भदरसा नगर पंचायत के चर्चित सामूहिक दुष्कर्म मामले में सपा नेता मोईद अहमद को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ से जमानत मिल गई है। न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की एकल पीठ ने गुरुवार को यह आदेश सुनाते हुए अभियुक्त की दूसरी जमानत याचिका मंजूर की। मामला बीते वर्ष 29 जुलाई 2024 का है, जब पूराकलंदर थाने में किशोरी की तहरीर पर मोईद अहमद और उसके नौकर राजू खान के खिलाफ गैंगरेप, धमकी और वीडियो बनाने जैसी गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ था।

गैंगरेप का आरोपी सपा नेता मोईद अहमद

मामले ने राजनीतिक और प्रशासनिक दोनों ही स्तरों पर भूचाल मचा दिया था। गिरफ्तारी के बाद प्रशासन ने आरोपी की बेकरी, फैक्ट्री और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पर बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया था, यह कहते हुए कि निर्माण अवैध था और सरकारी भूमि पर किया गया था।

कोर्ट में बचाव पक्ष की दलील थी कि 71 वर्षीय मोईद को राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के कारण फंसाया गया है। वहीं, सरकारी पक्ष ने विरोध करते हुए कहा कि आरोपी और उसके साथी ने किशोरी के साथ दरिंदगी कर उसका वीडियो बनाया, और वह मोबाइल फोन पुलिस ने बरामद कर लिया है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने कहा कि वह साक्ष्यों पर कोई टिप्पणी किए बिना केवल जमानत पर आदेश दे रही है।

मोईद की पहली जमानत अर्जी खारिज हो चुकी थी, लेकिन पीड़िता और उसकी मां की गवाही पूरी होने के बाद पुनः याचिका दायर करने की अनुमति दी गई थी।

अब अदालत से मिली राहत के बाद, मोईद की रिहाई की कानूनी प्रक्रिया शुरू हो गई है। जबकि सह–अभियुक्त राजू खान की जमानत याचिका अगली सुनवाई में विचाराधीन रहेगी। जमानत के आदेश के बाद अयोध्या में चर्चाओं का दौर गर्म है। एक पक्ष इसे न्याय की जीत बता रहा है तो दूसरा सियासी प्रभाव की ताकत मान रहा है।

भदरसा क्षेत्र के लंबे समय से प्रभावशाली सपा नेता रहे मोईद अहमद के खिलाफ यह केस अयोध्या की राजनीति और न्याय व्यवस्था दोनों के लिए कसौटी बन चुका है। अब सबकी निगाहें कोर्ट की आगे की कार्यवाही और उस किशोरी की न्याय यात्रा पर टिकी हैं। जिसने सत्ता, सियासत और डर के खिलाफ आवाज उठाई थी।

ये कैसा दीपोत्सव, भूखे-प्यासे लंगूरों के बीच अयोध्या की जगमगाहट

» पेटा और एडब्ल्यूबीआई को भेजी गई शिकायत, पशु प्रेमियों ने पूछा, क्या धर्म करुणा के बिना अधूरा है?

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

अयोध्या। भव्य दीपोत्सव की रोशनी के बीच अब अयोध्या में एक ऐसा साया मंडरा रहा है जो संवेदना को झकझोर देता है। स्थानीय कार्यकर्ताओं के अनुसार, दीपोत्सव-2025 के आयोजन में 9 लंगूरों को लखनऊ से पकड़कर अयोध्या लाया गया और उन्हें प्रमुख समारोह स्थलों के पास प्रदर्शन के रूप में रखा गया। इन लंगूरों के लिए न खाने-पीने की कोई उचित व्यवस्था थी, न ही चिकित्सकीय देखभाल प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, कई लंगूर बीमार दिखे, कुछ उल्टी करते देखे गए। राम की पैड़ी पर हज़ारों की भीड़, डीजे की धुनें, स्पीकरों का शोर और आसमान में आतिशबाज़ी ऐसे माहौल में इन लंगूरों को बाँधकर रखा गया।

जानवर विशेषज्ञों का कहना है कि यह उनके लिए अत्यंत तनावपूर्ण स्थिति है ।इस हालात पर पशु अधिकार कार्यकर्ता प्रज्ञा गुप्ता और यशवंत गौतम ने खुद स्थल पर जाकर लंगूरों की स्थिति देखी। उन्होंने तत्काल अयोध्या जिलाधिकारी और वन विभाग के डीएफओ प्रखर गुप्ता को ईमेल और ट्वीट के माध्यम से स्थिति की जानकारी दी। साथ ही, पेटा और एडब्ल्यूबीआई को भी औपचारिक शिकायत भेजी गई है। इस शिकायत

यह दीपोत्सव नहीं, यह जीवों की त्रासदी है। धर्म का नाम लेकर किसी जीव को डराना या भूखा रखना अधर्म है।

प्रज्ञा गुप्ता, पशु प्रेमी कार्यकर्ता

में लंगूरों की दुर्दशा, भूख–प्यास और भयावस्था की तस्वीरें और वीडियो भी संलग्न किए गए हैं। कार्यकर्ताओं की मांग है कि सभी 9 लंगूरों की तत्काल चिकित्सकीय जांच और सुरक्षित पुनर्वास कराया जाए।

यह जांच हो कि किस अनुमति या विभागीय आदेश के तहत इन्हें लाया गया। यदि कोई उल्लंघन पाया जाए तो पशु संरक्षण कानून और पीसीए एक्ट के तहत सख्त कार्रवाई हो। भविष्य में किसी भी धार्मिक या सरकारी आयोजन में वन्यजीवों के प्रयोग पर पूर्ण प्रतिबंध की घोषणा की जाए।

गुरुकुल परंपरा की धरोहर को आगे बढ़ाने का लिया संकल्प

» गुरु वशिष्ठ गुरुकुल विद्यापीठ वेद पाठशाला में सभा समिति का शपथ ग्रहण समारोह

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

अयोध्या ।अयोध्या स्थित श्रीगुरु वशिष्ठ गुरुकुल विद्यापीठ वेद पाठशाला में सभा समिति का शपथ ग्रहण समारोह वैदिक परंपरा और मंत्रोच्चारण के बीच बड़े ही उत्साहपूर्ण और गरिमामय वातावरण में सम्पन्न हुआ। नए पदाधिकारियों ने वेदिक विधि से पद एवं गोपनीयता की शपथ लेकर गुरुकुल परंपरा के संरक्षण और समाज सेवा का संकल्प लिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता श्री गुरु वशिष्ठ सेवा न्यास के अध्यक्ष आचार्य मनोज दीक्षित ने की। उन्होंने नवचयनित पदाधिकारियों को शपथ दिलाते हुए कहा कि गुरुकुल परंपरा भारतीय संस्कृति की आत्मा है, जो अनुशासन, संस्कार और राष्ट्र निर्माण का मूल आधार है।

समारोह में बतौर मुख्य अतिथि प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक डॉ. विक्रमा पाण्डेय और विशिष्ट अतिथि डॉ. राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय के पूर्व कुलानुशासक प्रो. आर.एन. रॉय उपस्थित रहे। दोनों अतिथियों ने कहा कि गुरुकुल प्रणाली केवल शिक्षा का माध्यम नहीं, बल्कि चरित्र और नैतिकता का आधार स्तंभ है, जिसे नई पीढ़ी तक पहुंचाना समय की आवश्यकता है। सभा समिति के प्रमुख आचार्य शिवबहादुर शास्त्री ने बताया कि समिति में 11 मुख्य पदाधिकारी और 5 विभाग प्रमुखों का चयन किया गया है। इनमें उत्कर्ष ब्रह्मचारी (अध्यक्ष), सिद्धांत ब्रह्मचारी, अनुज ब्रह्मचारी, चंद्रशेखर ब्रह्मचारी (उपाध्यक्ष), सौरभ ब्रह्मचारी (प्रधानमंत्री), सुधांशु ब्रह्मचारी, राजू ब्रह्मचारी (उपप्रधानमंत्री), पुष्पेंद्र ब्रह्मचारी, शिवांश ब्रह्मचारी (मंत्री), शौर्य ब्रह्मचारी (कोषाध्यक्ष), अथर्व व भोला ब्रह्मचारी (कार्यालय प्रमुख), समर्थ व सूर्यांश ब्रह्मचारी (सेनापति) शामिल हैं। समारोह में अयोध्या के विभिन्न गुरुकुलों के आचार्यगण, बटुक, प्रबंध समिति के पदाधिकारी और बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अंत में प्रबंधक आदर्श सिंह ऋषभ ने सभी अतिथियों और पदाधिकारियों का आभार व्यक्त किया। समारोह में भक्ति, अनुशासन और वैदिक गरिमा का अद्भुत संगम देखने को मिला।

10, 28, 205 छात्र-छात्राओं को 297.95 करोड़ की छात्रवृत्ति का अंतरण

प्रत्येक बच्चे में समाज को बदलने की क्षमताः योगी

बोले- छात्रवृत्ति से वंचित नहीं रहेगा कोई भी छात्र

» वरिष्ठ संवाददाता, स्वराज इंडिया न्यूज।

सीएम योगी आदित्यनाथ ने छात्र-छात्राओं को बड़ी सौगात दी। दशमोत्तर व पूर्वदशम छात्रवृत्ति वितरण कार्यक्रम के अंतर्गत एक साथ 10 लाख 28 हजार 205 विद्यार्थियों को 300 करोड़ की छात्रवृत्ति राशि डीबीटी के माध्यम से सीधे उनके बैंक खातों में प्रेषित की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा, इससे पहले भी विजयादशमी के अवसर पर बड़ी संख्या में विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति दी गई थी।

पहले छात्रवृत्ति वितरण प्रक्रिया में भेदभाव, विलंब और भ्रष्टाचार जैसी समस्याएं आम थीं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में टेक्नोलॉजी आधारित डीबीटी प्रणाली लागू होने से अब पात्र छात्रों के खाते में राशि सीधे पहुंच रही है। अब छात्रवृत्ति वर्ष में एक बार नहीं बल्कि दो चरणों में (अक्टूबर और जनवरी में) दी जाएगी, ताकि छात्रों को समय पर सहायता मिले। वर्ष 2016-17 तक जहां केवल 8.64 लाख विद्यार्थी छात्रवृत्ति से लाभान्वित होते थे, वहीं अब यह संख्या 62 लाख तक पहुंच गई है।

पारदर्शी और तकनीक आधारित व्यवस्था

सीएम योगी ने कहा, सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि कोई भी पात्र छात्र छात्रवृत्ति से वंचित न रहे। गत वर्ष जिन विद्यार्थियों को संस्थानों की लापरवाही या पोर्टल की त्रुटियों के कारण छात्रवृत्ति नहीं मिल पाई थी, उनके लिए पोर्टल को पुनः सक्रिय किया गया है। जैसे ही डेटा एंट्री पूरी होगी, एक विशेष समारोह में उन्हें भी डीबीटी के माध्यम से राशि दी जाएगी। हमारा लक्ष्य स्पष्ट है कि प्रदेश का कोई भी बच्चा शिक्षा के अधिकार से वंचित न रहे, हर छात्र अपने सपनों की उड़ान भर सके।

सीएम योगी ने भारत रत्न बाबा साहब डॉ. भीमराव आंबेडकर का उल्लेख करते हुए कहा, बाबा साहब ने कहा था कि पढ़-लिखकर ही हम स्वावलंबी बन सकते हैं और समाज के लिए कुछ कर सकते हैं। उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि कठिन परिस्थितियों में भी बाबा साहब ने शिक्षा के बल पर अपनी राह बनाई। आज हमारे पास संसाधनों की कमी नहीं, आवश्यकता है मेहनत, अनुशासन और लगन की। पिछले आठ वर्षों में 4 करोड़ 27 लाख से अधिक विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति का लाभ दिया गया है। 2016-17 से पहले की सरकारों ने अनुसूचित जाति और जनजाति सीएम योगी ने कहा,छात्रों की छात्रवृत्ति रोक दी थी, लेकिन हमारी सरकार ने न केवल वह राशि जारी की बल्कि दो वर्षों की छात्रवृत्ति एक साथ दी। हमारा स्पष्ट संकल्प है कि किसी भी विद्यार्थी के साथ भेदभाव नहीं होगा। ईमानदारी, पारदर्शिता और समान अवसर हमारी सरकार की प्राथमिकता है।

सशक्तिकरण की नई पहल

सीएम योगी ने कहा,प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में प्रदेश में शिक्षा-सशक्तिकरण के लिए कई नई पहलें की गई हैं। अटल आवासीय विद्यालय के माध्यम से सभी 18 कमिश्नरी में विद्यालय संचालित किए जा रहे हैं, जहां श्रमिक परिवारों के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, आवास और भोजन की सुविधा मिल रही है। आश्रम पद्धति विद्यालय के अंतर्गत अनुसूचित जाति वर्ग के छात्रों के लिए उत्कृष्ट शिक्षा, आवास और भोजन की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है।

कस्तूरबा बालिका विद्यालय के माध्यम से गरीब और वंचित वर्ग की बालिकाओं को इंटरमीडिएट स्तर तक निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जा रही है।

सामाजिक सुरक्षा का कदम

सीएम योगी ने कहा, समाज कल्याण विभाग के माध्यम से प्रदेश के 1 करोड़ 5 लाख परिवारों को 12,000 वार्षिक पेंशन डीबीटी के जरिए दी जा रही है। पहले 300 मासिक पेंशन छह महीने में दी जाती थी, जिसमें बिचौलिये हिस्सा खा जाते थे। हमारी सरकार ने इसे बढ़ाकर अब 1,000 प्रति माह किया है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत अब तक 4 लाख से अधिक बेटियों के विवाह कराए जा चुके हैं। प्रत्येक विवाह हेतु 1 लाख की सहायता राशि दी जाती है।

दहेज उत्पीड़न में घूस मांगना पड़ा भारी, महिला एसएचओ गिरफ्तार

आरोपियों का नाम निकालने का दिया था ऑफर

वाराणसी

महिला एसएचओ सुमित्रा देवी

» वरिष्ठ संवाददाता, स्वराज इंडिया ब्यूरो।

वाराणसी। वाराणसी में आज शुक्रवार को एक चौंकाने वाली घटना सामने आई। एंटी करप्शन टीम ने महिला थाना प्रभारी निरीक्षक सुमित्रा देवी को 10 हजार रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। यह कार्रवाई तब हुई, जब सुमित्रा देवी पर दहेज उत्पीड़न के एक मामले में आरोपियों का नाम निकालने के लिए रिश्वत मांगने का आरोप लगा। इस घटना ने पुलिस विभाग में भ्रष्टाचार को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

एंटी करप्शन टीम को एक दिन पहले शिकायत मिली थी कि सुमित्रा देवी दहेज उत्पीड़न के मामले में कुछ व्यक्तियों का नाम केस से हटाने के लिए प्रति व्यक्ति निश्चित राशि की मांग कर रही थीं। शिकायतकर्ता ने बताया कि जिन लोगों का नाम मामले में शामिल किया गया था, उन्हें गलत तरीके से फंसाया गया था। इस सूचना के आधार पर एंटी करप्शन टीम ने त्वरित कार्रवाई की और एक जाल बिछाया। शुक्रवार सुबह महिला थाने में ही सुमित्रा देवी को 10 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए पकड़ लिया गया।

» रिश्वतखोर अधिकारियों ने पुलिस की कार्यशैली पर खड़े किए सवाल।

टीम ने सुमित्रा देवी को हिरासत में ले लिया और उन्हें कैंट थाने लाया गया, जहां उनके खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत मामला दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू की गई। बताया जाता है कि सुमित्रा देवी इससे पहले राजातालाब थाने में भी प्रभारी रह चुकी हैं। उनकी गिरफ्तारी से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है, और इस मामले ने स्थानीय लोगों के बीच भी चर्चा का विषय बना हुआ है।

यह घटना पुलिस की कार्यप्रणाली और निष्पक्षता पर सवाल उठाती है। दहेज उत्पीड़न जैसे संवेदनशील मामलों में रिश्वतखोरी का यह मामला समाज में पुलिस के प्रति विश्वास को और कमजोर कर सकता है। एंटी करप्शन टीम ने इस कार्रवाई को गुप्त रखा था ताकि सबूतों के साथ आरोपी को पकड़ा जा सके। इस मामले में आगे की जांच जारी है, और यह देखना बाकी है कि क्या अन्य लोग भी इस रिश्वतखोरी के खेल में शामिल हैं।

स्थानीय लोगों का कहना है कि इस तरह की घटनाएं पुलिस और जनता के बीच की दूरी को बढ़ाती हैं। वहीं, पुलिस विभाग ने इस मामले में कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। सुमित्रा देवी के खिलाफ दर्ज मामले में भ्रष्टाचार के आरोपों की गहन जांच की जाएगी, ताकि पूरे प्रकरण का सच सामने आ सके।

हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट सख्त

सभी मामलों में सीबीआई जांच का आदेश नहीं देंगे

सचिवालय में हुए घोटालों की जांच रुकवाने यूपी सरकार ने किया था शीर्ष अदालत का रुख

» वरिष्ठ संवाददाता, स्वराज इंडिया ब्यूरो।

नई दिल्ली। यूपी सचिवालय में 186 पदों पर हुई घोटाले की सीबीआई जांच रुकवाने के लिए योगी सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। दरअसल, 2022-23 में यूपी सचिवालय में 186 पदों पर भर्ती निकली थी, जिसमें हर पांचवा सफल उम्मीदवार बीजेपी मंत्री का रिश्तेदार या अधिकारी का रिश्तेदार था। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इसे बड़ा भर्ती घोटाला मानते हुए सीबीआई जांच का आदेश दिया था, अब सुप्रीम कोर्ट ने जांच रोक दी।

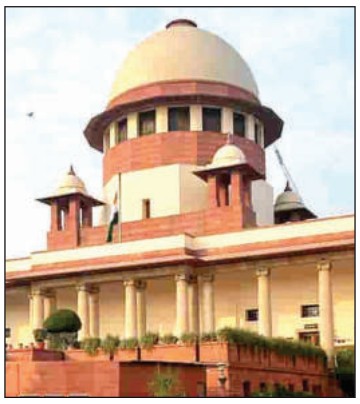

शीर्ष न्यायालय ने गुरुवार को एक मामले की सुनवाई के दौरान महत्वपूर्ण टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायालयों और खुद को चेतावनी देते हुए कहा कि किसी भी मामले में सीबीआई जांच का आदेश देना अंतिम उपाय होना चाहिए, न कि इसे एक नियमित प्रक्रिया का हिस्सा बना लिया जाए। इस टिप्पणी के दौरान कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सीबीआई जांच का सहारा तभी लिया जाना चाहिए, जब अन्य सभी विकल्प समाप्त हो जाएं और मामले की निष्पक्षता पर भी सवाल खड़े हों।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सांविधानिक अदालतों को सामान्य या रोजमर्रा के मामलों में सीबीआई जांच का आदेश नहीं देना चाहिए। ऐसा आदेश केवल खास और गंभीर परिस्थितियों में ही सावधानीपूर्वक दिया जाना चाहिए। जस्टिस जे.के. माहेश्वरी और जस्टिस विजय बिश्नोई की बेंच ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक आदेश को रद्द करते हुए यह टिप्पणी की। हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश विधान परिषद कर्मचारियों की भर्ती प्रक्रिया में कथित हेराफेरी की जांच सीबीआई से कराने का निर्देश दिया था। शीर्ष कोर्ट ने कहा कि अदालत के पास केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को जांच का आदेश देने की शक्ति जरूर है। लेकिन इसका उपयोग बहुत सीमित, सोच-समझकर और केवल असाधारण परिस्थितियों में किया जाना चाहिए।

बेंच ने कहा, यह कोर्ट चेतावनी देती है कि सीबीआई जांच का आदेश देना कोई सामान्य प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए। केवल इसलिए कि कोई पक्ष राज्य पुलिस पर कुछ आरोप लगा रहा है या उसके प्रति अपनी व्यक्तिगत अविश्वास की भावना जाहिर कर रहा है, तो यह सीबीआई जांच का आधार नहीं बन सकता।